ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 10, Issue 5, May 2020 Impact Factor 5.13 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और सामाजिक बदलाव

डॉ0 सुशील कुमार
सहायक प्रोफेसर–समाजशास्त्र
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिन्दकी, फतेहपुर।

स्वस्थ जीवन सभी का अधिकार है और स्वास्थ्य समस्या के निदान के लिये सरकार एवं संस्थाओं का दायित्व है की वे सुविधाओं का अनवरत विस्तार करें और किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य से संबंधित डिजिटल मिशन सभी तक आसानी से सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के द्वारा आमजन आसानी से लाम प्राप्त कर सके और घर बैठे उसे उच्चस्तरीय इलाज प्राप्त हो यही मिशन का उद्देश्य है।

भारतीय दर्शन का यह सूत्र है की हमारा जीवन स्वस्थ एवं काया निरोगी हो लेकिन कोरोना काल और इससे पहले भी देश की स्वास्थ्य सेवाएं कई कारणों से सवालों के घेरे में रही है। खासतौर से इसलिए, क्योंकि खुद को सेहतमंद बनाए रखने और कोई बीमारी होने पर इलाज की कोशिशों को निजी मान लिया गया है। यानी अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या कोई इलाज कराना चाहते है तो इसमें समाज या सरकार से ज्यादा भूमिका व्यक्तिगत होती है। शायद यही वजह है कि बीमार पड़ने पर कई लोग अपने जीवन भर की जमापूजी तक गंवा बैठते हैं। बहुत से मामलों में तो बीमारी का पता नहीं चलने और सही इलाज नहीं मिलने पर मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है या जीवन भर कोई अपंगला डोलनी पड़ती है, लेकिन अब ये हालात बदल सकते हैं। इसकी वजह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, जिसकी देश में हाल में शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2020 को लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। अभी यह अंडमान–निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमनदीव लद्दाख और लक्षद्वीप में चल रही है। अब पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। इस मिशन का मसकद यह है कि हर शख्स की हेल्थकेयर सर्विस देने वाले संस्थानों तक पहुंच को आसान बनाया जाए। इसे लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 7 वर्षों में, देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का ज अभियान चल रहा है, वह आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन क शुरुआत हो रही है, जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है आज देश में 130 करोड आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड इंटरनेट यूज और करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। इतना

बड़ा कनेक्टेड इन्फ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है ये डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज, पारदर्शी तरीके से सामान्य भारती तक पहुंचा रहा है। कोरोना काल में टेलिमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई–संजीवनी माध्यम से अब तक लगभग सवा करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। ये सुविधा हर रोज देश दूर–सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से कनेक्ट कर रही है। आयुष्मान भारत के की बहुत बहादूर की है। अभी तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है। इसमें भी आधी लाभार्थी, हमारी माताएं, बहने, बेटिया है। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जो एक तरह का पहचान पत्र होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेस, इंटरनेट ऑफ चिंग्स, ब्लॉकचैन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थितिकी तत्र को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इन तकनीकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी किया जा सकता है। इसके अलावा लागत में कमी करने से लेकर सेवाओं को सुविधाजनक भी इन तकनीकों के माध्यम से बनाया जा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत डिजिटल बुनियादी ढांचे का सफलतापूर्वक उपयोग करके लाभार्थियों की पहचान से लेकर उनको अस्पताल में प्रवेश एवं उपचार करवाने तक एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म से एंड टू एंड सेवाएं प्रदान की गई है। इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन के लिए भी किया जा सकता है। जिससे कि नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, सरकार एवं शोधकर्ताओं को सशक्त बनाया जा सके एवम अंतर संचालित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा सके। वर्तमान सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा जैसे कि आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मशीन के कार्यान्वयन में सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा डॉक्टरी, स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल रूप से पहचानना, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की सुविधा, गैर आवासीय अनुबंधों को सुनिश्चित करना, कागज रहित भुगतान करना, डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना आदि जैसी सुविधाएं इस योजना के माध्यम से प्राप्त होगी। हेल्थ कार्ड यह भी बताएगा कि उस व्यक्ति को किन–किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। रोगी को आयुष्मान भारत के तहत इलाज की सुविधाओं का लाभ मिलता है या नहीं, यह भी पता चल सकेगा। पब्लिक हास्पिटल, कम्युनिटी हेल्य सेंटर, हेल्थ एड वेलनेस सेंटर या पैसा हेल्थकेयर प्रोवाइडर जो नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री से जुड़ा हो, किसी व्यक्ति की हेल्थ आइडी बना सकता है। पीएम डीएचएम का लक्ष्य टेक्नोलाजी के माध्यम से भारत में हेल्थ सर्विसेज में सुधार लाना है। हेल्थकेयर डाटा के बेहतर एक्सेस से यह सभव हो पाएगा। इसमें भारतीय

नागरिकों, स्वास्थ्य पेशेवरों, सार्वजनिक अस्पतालों के साथ–साथ निजी क्षेत्र के संस्थानों के बीच सेहत की जांच, निगरानी और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने वाला एक पुख्ता नेटवर्क बन सकेगा। इससे लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता आ सकती है और बीमारियों के त्वरित एवं सटीक इलाज की व्यवस्था बन सकती है। कोई बीमारी होने पर इलाज नहीं करवा पाने की तकलीफ वही जान सकता है, जिसे इससे जुड़ाना पड़ता है। सवाल सिर्फ कोरोना के संक्रमण या दिल के मर्ज या कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों और उनके महंगे इलाज एवं दवाओं की उपलब्धता का ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि सदी–जुकाम जैसी आम बीमारियों का इलाज कराने और उनके लिए दवा खरीद पाने की हैसियत देश के जाम तबके की नहीं है। कई बार मरीजों को तब ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, जब उनकी बीमारी की सही जांच नहीं होती। इससे उन्हें सही और सस्ता इलाज नहीं मिल पाता है। यही नहीं, एक बार बीमार होने के बाद एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की दौड़–धूप करते मरीज और उनके तीमारदार डाक्टरों के निर्देश पर एक ही टेस्ट कई बार करते हैं। इसके बारियों के इलाज कर रिकार्ड मौजूद नहीं होने पर कई बार गलत इलाज की चपेट में भी आ जाते हैं। ऐसे में मजे से बड़ी समस्या उसके निदान की प्रक्रिया हो जाती है। यह तथ्य भी कई बार सामने आ चुके हैं कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों के इलाज में ही गरीब हुआ जा रहा है, क्योंकि अक्सर उन्हें यही नहीं पता चलता है कि आखिर उन्हें हुआ क्या है? किस बीमारी का क्या इलाज है और कहा इलाज हो सकता है? इसकी जानकारी नहीं होने पर मरीज गलत हाथों में पड़ आते हैं। ऐसे में सही इलाज की पहली सौदी मरीज और उसके तीमारदार को इसकी जानकारी मिलना है कि आखिर बीमारी क्या है या मरीज को इससे पहले क्या मर्ज था और उसका क्या इलाज था? आमतौर पर ऐसे सारे रिकार्ड रखते की जिम्मेदारी व्यक्तिगत मानी जाती है, लेकिन सरकार के स्तर पर महसूस किया गया कि अगर लोगों की बीमारियों का कोई डाटाबेस तैयार हो सके और संबंधित जानकारियों को एक डिजिटल कार्ड में समाहित किया जा सके तो इस क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हो सकता है।

भारत ऐसी व्यवस्था करने वाला दुनिया का पहला देश नहीं है, बल्कि कई अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है। जैसे ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया में डिजिटल हेल्थ रिकार्ड की व्यवस्था और अमेरिका में कायम नेशनल हेल्थ सांवस आदि का इस संबंध में अध्ययन किया गया। उल्लेखनीय है कि डिजिटल हेल्थ कार्ड जैसी योजना की प्रेरणा के पीछे एक भूमिका आयुष्मान भारत योजना की है। तीन साल पहले 25 सितंबर, 2018 को देश के 25 राज्यों में औपचारिक रूप से आयुष्मान योजना को जब लागू किया गया तो यह उम्मीद जगी थी कि अब देश के वंचित, उपेक्षित और गरीब लोगों को बीमारियों के इलाज में कोई समस्या नहीं होगी। इलाज की इन योजनाओं को दरिद्र नारायण की सेवा कहा जा सकता

है। खासतौर से यह देखते हुए कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही लचर हालत में है। यहां सरकारी चिकित्सा सेवाओं में अक्सर लापरवाही, संसाधनों का दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा जाता है। निजी क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं के मानक तय नहीं हैं। निजी अस्पताल जांच, टेस्ट, इलाज और दवाओं आदि के नाम पर अनाप–शनाप रकम वसूलते है। इसलिए डिजिटल हेल्थ कार्ड और नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से तमाम अनियमितताओं पर रोक लगने की उम्मीद की जा रही है, पर क्या यह योजना संच में धांधलियों की रोकथाम में मददगार साबित हो सकेगी और कोई समस्या नहीं खड़ी करेगी?

यूनिक हेल्थ कार्ड की बात है तो अभी इसके कई फायदे एक साथ दिख रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक बार बीमारी की कोई जांच हो जाने और उसका इलाज शुरू हो जाने के बाद देश में कहीं भी जाने पर कोई जांच रिपोर्ट, डाक्टर की पर्ची, बीमारी के पुराने रिकार्ड आदि संभाल कर रखने और ले जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सभी सूचनाएं हेल्थ कार्ड में दर्ज होगी और चिकित्सक किसी मरीज की आइडी से जान जाएंगे कि मरीज पहले किन बीमारियो की चपेट में रहा है और उसका किस स्तर पर कहां एवं कितना इलाज हुआ है। आधार कार्ड या मोबाइल नंबर के माध्यम से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की वेबसाइट पर हेल्य आइडी शीर्षक के तहत सभी जानकारियां देकर यह कार्ड बनाया जा सकता है और इससे जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठया जा सकता है। हेल्थ कार्ड के माध्यम से लोग किसी भी राज्य में अस्पतालों, पैथ लैब और फार्मा कंपनियों में अपनी सेहत से जुड़ी जानकारियां अपनी मजी के हिसाब से ले सकेंगे। यानी इनमें कोई बाहरी व्यक्ति उनकी मंजूरी के बिला दखल नहीं दे सकेगा। हेल्थ कार्ड इस योजना का एक छोटा, किंतु सुविधापूर्ण हिस्सा है। इस योजना के फायदों को समझना हो तो इसे समग्रता में देखना होगा। केंद्रीय सर्वर से जुड़े रहने के कारण मरीज, डाक्टर, अन्य स्वास्थ्यकमी, अस्पताल और सरकार तक व्यक्ति की मंजूरी के साथ जरूरी जानकारियां जुटा सकेंगे और नागरिकों को स्वस्थ रखने के मिशन को साकार किया जा सकेगा। इसके अलावा नौति निर्माताओं एवं कार्यक्रम प्रबंधकों के पास डाटा की बेहतर पहुंच होगी। जिससे कि सरकार को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा भूगोल एवं जनसंख्या आधारित निगरानी और स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं नीतियों के कार्यान्वयन करने में भी सहायता प्राप्त होगी। शोधकर्ता भी अध्ययन एवं मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकेंगे। इसके अलावा यह योजना शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं एवं प्रदाताओं के बीच एक व्यापक फीडबैक लूट की सुविधा प्रदान करेगी।

आयुष्मान भारत अभियान का यह डिजिटल मिशन असल में अस्पताली प्रक्रियाओं को सरल बनाने

की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिजिटल राह पर बढ़ते देश की एक झलक तो मिलती ही है। साथ में खर्च, गलत इलाज समेत जनता की सेहत से जुड़ी तमाम चिंताओं के समाधान की राह भी खुलती है। एक कल्याणकारी शासन व्यवस्था में जनता के हित की योजनाएं ऊपरी तौर पर काफी लुभावनी प्रतीत होती हैं, लेकिन कई बार उनकी जमीनी हकीकत काफी अलग होती है और अनेको चुनौतियाँ सामने आती हैं। भ्रष्टाचार और दलाली का नेटवर्क स्वास्थ्य सेवा की सबसे बड़ी कमी हैं। स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टर सामाजिक जीवन में भगवान माने जाते हैं लेकिन आज उनकी पहचान श्वेतवशन अपराधियों के रूप में होती है अक्सर इस तरह का उदाहरण आर्य दिन देखने को मिकता है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और हेल्थ कार्ड को इन सवालों की रोशनी में देखे तो सबसे पहला सवाल इसमें जुटाए जाने वाले डाटा की सुरक्षा यानी साइबर सेंधमारी का उठता है। सरकार यूं तो दावा करती है कि वह इस डाटा की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर रही है, लेकिन किसी सर्वर पर जमा किए जाने वाले सरकारी डाटा में सेंध लगाना अब कई हैकरों की नजर में सबसे आसान काम है। आधार कार्ड के जुड़े डाटा पर हाथ साफ करने की कोशिशों के बारे में पहले भी कई दावे किए गए हैं, जिनसे सरकार ने हमेशा इन्कार किया है, पर इन आशंकाओं को आज भी साइबर विशेषज्ञ पूरी तरह खारिज नहीं कर पाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर सेहत से जुड़े रिकार्ड जब तक एक व्यक्ति के पास है, तब तक कोई खतरा नहीं, लेकिन जैसे ही वह रिकार्ड किसी साझा सर्वर पर पहुंचता है तो ये सारी आशंकाएं सिर के बल खड़ी हो जाती है।

निष्कर्ष : शोध पत्र से स्पष्ट है की स्वास्थ्य सुविधाओं का सभी तक पहुँच हो और एक सार्वभौमिक रिकार्ड हमेशा उपलब्ध हो जिससे किसी भी विमार व्यक्ति का आसानी से रोगों का इलाज किया जा सके और किसी भी समय कहीं से निदान प्राप्त किया जा सके। आज भारत में डिजिटल उपकरणों की सुविधा बढी है और इसका स्वास्थ्य सुविधाओं में उपयोग काफी प्रभावकारी है। लेकिन डिजिटल तकनीक की कुछ समस्या है। स्वस्य व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और आयुष्यमान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वस्थ काया के लिये एक क्रांतिकारी योजना है।

सन्दर्भ :

1- https://havbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/pm-narendra-modi-launches-pm-digital-health-mission-know-detail-here/articleshow/86548309.cms / 27 Sep 2021

2- https://www.livehindustan.com/business/story-prime-minister-digital-health-mission- launched-now-every-citizen-will-have-a-health-id-know-everything-about-it- 4677541.html/27 Sep 2021

3- आयुष्मान भारत डिजिटल मिषन 2021।

4- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सेव होगी जानकारी, बनेगा सबका हेल्थ अकाउंट https://www.naidunia.com/national-ndhm-pm-modi-will-start-national-digital-health-mission-from-today-know-its-special-things-7060661